1

UPSC : सिविल सेवा परीक्षा

GS Paper – III : INTERNAL SECURITY

by

Dr. S. S. Pandey

2

Dr. S. S. Pandey

Money- Laundering and its Prevention

3

भारत में मनीलॉन्ड्रिंग

- अर्थ
- प्रक्रिया
- भारत में स्वरूप एवं प्रचलित तकनीकें
- मनीलॉन्ड्रिंग के दुष्परिणाम
- मनीलॉन्ड्रिंग रोकने हेतु किए गए प्रयास
- मनीलॉन्ड्रिंग के नियंत्रण की बाधाएँ
- मनीलॉन्ड्रिंग रोकने हेतु सुझाव

4

मनीलॉन्ड्रिंग का अर्थ

5

काला धन

6

मनी-लॉन्ड्रिंग एक अवैध तरीके से प्राप्त काला धन को वैध धन के रूप में परिवर्तित करने की एसी प्रक्रिया है जिसे आर्थिक लेन-देन के जटिल चक्र में डालकर उसे वैध बनाया जाता है

7

मनीलॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया

8

मनीलॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया

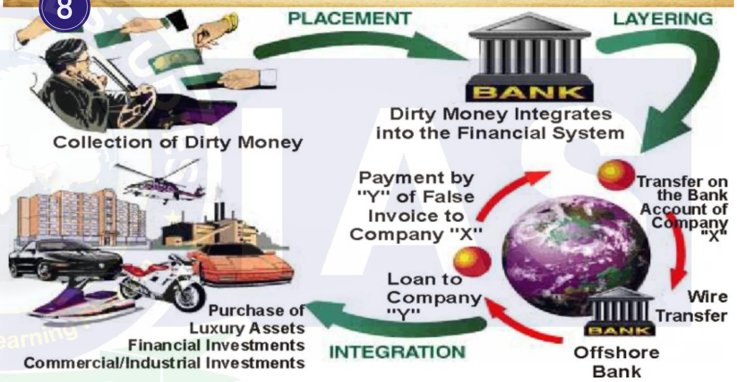

9

1. **Placement** – इसके अन्तर्गत अवैध धन को उसके स्रोत से दूर किया जाता है
2. **Layering** – इसके अन्तर्गत स्रोत से दूर किय गय अवैध धन को आर्थिक लेन-देन के जटिल प्रक्रिया में डाल दिया जाता है
3. **Integration** – इसके अंतर्गत आर्थिक लेन-देन की प्रक्रिया में डाले गय धन को वैध रूप से अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है

10

भारत में मनीलॉन्ड्रिंग का स्वरूप

11

1.

विश्व की Money Laundering की कुल रकम विश्व के GDP का 2.5% है (IMF)

12

2.

भारत में 600 M $ की Money Laundering जो भारत की GDP का 4% (IMF)

13

3.

उदाहरण–
कुमार मंगलम बिड़ला,
ललित मोदी,
विजय माल्या,
हसन अली खान का केस

14

4.

भारत में काला धन

- IMF — GDP का 50%
- CBI — 25 लाख करोड

15

भारत में मनीलॉन्ड्रिंग की प्रचलित तकनीक

16

ट्रस्ट के माध्यम से मनीलॉन्ड्रिंग

17

1. HM के सैयद सलाऊद्दीन के पास काला धन 13 करोड →
2. सलाऊद्दीन द्वारा 'जम्मू-कश्मीर राहत ट्रस्ट' का निर्माण ↓
3. सलाऊद्दीन द्वारा 13 करोड काला धन को टुकड़ों में दान के रूप में ट्रस्ट में जमा किया गया →
4. सैयद सलाऊद्दीन का 13 करोड काला धन का सफेद धन के रूप में शोधन

18

Shell Company या काल्पनिक खरीद बिक्री द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग

19

1. Mr. X के पास काला धन 10 करोड →
2. Mr. X द्वारा Coaching Institute खोला गया →
3. कोचिंग में कुल वास्तविक नामांकन/आय 1000 × 50000 = 5 करोड ↓
4. कोचिंग में कुल प्रदर्शित छद्म नामांकन / आय 3000 × 50000 = 15 करोड →
5. 15 करोड पर कर भुगतान →
6. Mr. X के 10 करोड काला धन सफेद धन के रूप में शोधन

20

हवाला एवं Round Tripping द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग

21

1. US President निक्सन के पास वाटरगेट कांड से प्राप्त काला धन
2. निक्सन द्वारा हवाला के माध्यम से उस धन को मैक्सिको पहुँचाया गया
3. निक्सन द्वारा उस पैसे का मैक्सिको की कंपनी में निवेश
4. निक्सन द्वारा उस धन को वैध रूप से मियामी की एक कंपनी द्वारा USA में प्राप्ति
5. निक्सन का काला धन का सफेद धन के रूप में शोधन

22

Back to Back Loan द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग

23

1. USA के गैंगेस्टर मेयर लेंस्की के पास 1 अरब डॉलर काला धन
2. लेंस्की द्वारा हवाला के माध्यम से उस धन को स्वीटजरलैंड पहुँचाया गया
3. लेंस्की द्वारा स्वीस बैंक में कई खाते खोलकर उसमें जमा किया गया
4. लेंस्की द्वारा स्वीस बैंक से उस धन के बदले में USA में लोन की प्राप्ति
5. लेंस्की का 1 अरब डॉलर काला धन का सफेद धन के रूप में शोधन

24

Casino / घुड़दौड़ द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग

25

1. Mr. D के पास भारत में काला धन
2. Mr. D द्वारा काला धन को घुड़दौड़ में सट्टे के रूप में (नगद) प्रयोग
3. Mr. D द्वारा उस धन को चेक के रूप में प्राप्ति और उसे जीते हुए रकम के रूप में घोषणा
4. Mr. D का काला धन का सफेद धन के रूप में शोधन

26

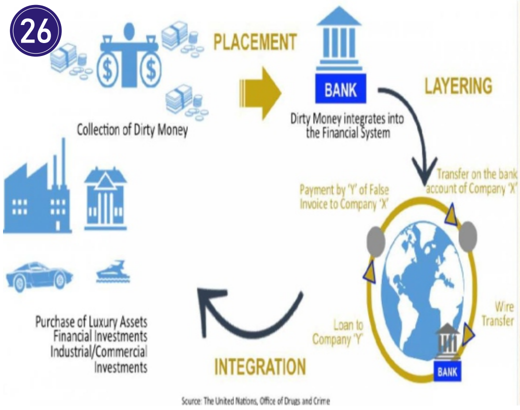

1.

ट्रस्ट के माध्यम से मनीलॉन्ड्रिंग

फर्जी दान दाताओं से छोटे-छोटे रकम प्राप्त कर Money Laundering करना

(हिजबुल मुजाहीदीन के सय्यैद सलाउदीन का केस– 'जम्मू-कश्मीर राहत ट्रस्ट' में 13 करोड की प्राप्ति)

27

2.

Shell Company या काल्पनिक खरीद बिक्री द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग

काल्पनिक कम्पनी का निर्माण और काल्पनिक खरीद बिक्री पर Income दिखाकर और उस पर Tax देकर Money Laundering

28

3.

हवाला (धन का अवैध हस्तान्तरण) तथा राउण्ड ट्रीपिंग के रूप में Money Laundering

29

Direct Tax Avoidance Agreement (DTAA)

दो देशों के बीच एक एसी संधि जिसके तहत किसी भी धन पर दोनों देशों में से किसी भी देश में एक बार Tax देने पर (मुख्यतः कम्पनी का पता जिस देश का है उस देश में ही Capital Gain Tax) उस धन पर दोबारा Tax नहीं देना पड़ता है।

(भारत का 89 देशों के साथ DTAA जिनमें 85 के साथ लागू)

30

Tax Heaven Country

वह देश जहां किसी भी आय पर Tax नहीं लगता है या बहुत कम लगता है

[जैसे– मॉरीशस, लग्जम्बर्ग, स्विटजरलैंड, हॉगकॉग, सिंगापुर आदि]

एसे देश Tax में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते हैं ना ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं

31

4.

Back to Back Loan द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग

↓

दो देशों की कम्पनी या बैंक के द्वारा अपने-अपने मुद्रा में Loan प्रदान करना और इस प्रक्रिया से Money Laundering करना

↓

(गैंगेस्टर मेयर लेंस्की का केस)

32

5.

कैसीनो / घुड़दौड़ द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग

↓

कैसीनो या घुड़दौड़ में नगद लगाकर तथा उसे चेक में प्राप्त करके और उसे जीता हुआ रकम बताकर Money Laundering करना

(हसन अली खान का केस)

33

6.

स्मर्फिंग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग

↓

बैंक लिमिट से कम रकम कई बार जमा करके

Money Laundering करना

34

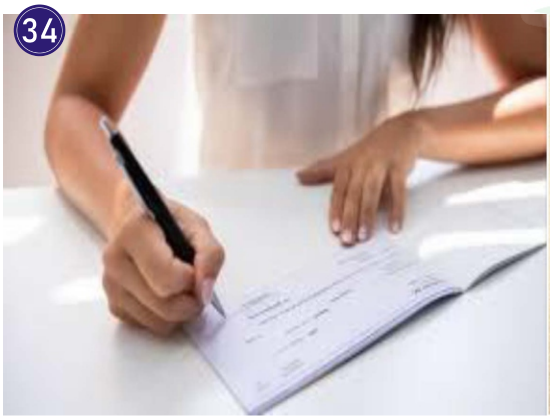

7.

Third Party Cheque

↓

किसी दूसरे के नाम से चेक काटकर भुगतान करके Money Laundering करना

35

मनीलॉन्ड्रिंग के दुष्परिणाम / समस्यात्मक पहलू

↓

36

(a) आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव

↓

37

1. आतंकवाद एवं उग्रवाद का वित्तपोषण एवं बढ़ावा
2. संगठित अपराध को बढ़ावा
3. मादक पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी को बढ़ावा
4. गैरकानूनी गतिविधि को प्रोत्साहन
5. भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को बढ़ावा

38

(b) आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव

↓

39

1. कर चोरी को प्रोत्साहन फलतः सरकारी राजस्व में कमी
2. काले धन में वृद्धि फलतः अर्थव्यवस्था में असंतुलन फलतः विकास एवं निवेश पर नकारात्मक प्रभाव

40

3. बाजार में कृत्रिम माँग (Artificial Demand) को प्रोत्साहित करके मंहगाई में वृद्धि
4. संगठित अपराध का अर्थव्यवस्था में प्रवेश एवं आर्थिक स्थिरता को खतरा

41

(c) सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव

42

1. भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को प्रोत्साहन फलत: समाज में नैतिकता का पतन

2. समाज में गैर-कानूनी गतिविधि एवं अपराध में वृद्धि फलत: कानून व्यवस्था की समस्या

3 राजनीतिक स्थिरता को खतरा फलत: वैध रूप से काय करने वाले लोगों का मनोबल कमजोर

43

भारत में मनीलॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास

44

(A) अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

45

1.

1988

बैंकिग नियमों पर बेसल समिति

चार प्रमुख निर्देश / सिद्धान्त जारी

46

(i) KYC
(ii) कानून का पालन
(iii) कथन का अनुपालन
(iv) कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ सहयोग

47

2.

1989

वित्तीय कार्यवाही दल (Financial Action Task Force)

48

G-7 राज्यो द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय निकाय

उद्देश्य

मनीलॉन्ड्रिग एवं आतंकवाद के वित्तीय स्रोत को रोकना

इस हेतु यह दो तरह की सूची जारी करती है–

1. Black List
2. Grey List

35 देश सदस्य (जून 2010 में भारत सदस्य)

49

50

इसमें 164 देशों के FIU शामिल है (मई 2007 में भारत सदस्य)

उद्देश्य

वैश्विक स्तर पर होने वाले संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन की सूचनाओं का समन्वय और पारस्परिक आदान-प्रदान

51
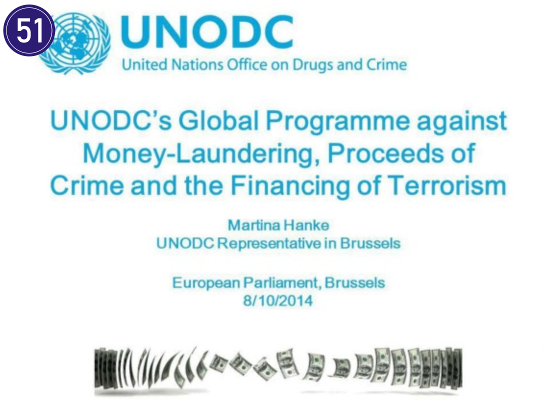

4.

1997

Global Programme Against Money Laundering

56

8.

2004

यूरेशियन समूह
↓
FATF का एक सहयोगी क्षेत्रीय समूह

(42 देश सदस्य)

52

5.

प्रमुख UN - Convention-
↓

57

9.

2016

भारत का मनी-लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में विभिन्न देशों के साथ समझौता
↓

53

(i) UN Convention Against illicit traffic in Narcotics Drugs- 1988 or (UN Convention on Drugs)

(ii) UN Convention on Financing of Terrorism - 1999

(iii) UN Convention against Organised Crime - 2000

(iv) UN Convention Against Corruption - 2003

58

(i)

2016

भारत – मॉरिशस समझौता तथा 30 दिसम्बर 2016 के भारत-सिंगापुर समझौता द्वारा DTAA में संशोधन– जिसके तहत – DTAA के तहत मिली छूट समाप्त

[Note- 2015-2016 में कुल 29.4 अरब डॉलर FDI जिसमें मॉरिशस एवं सिंगापुर की हिस्सेदारी 17 अरब डॉलर रही]

54

6.

2012

Money Laundering अन्वेषण हेतु

International Money Laundering Information Network

(UN द्वारा स्थापित)

59

(ii)

June 2017

DTAA में संशोधन हेतु पुर्तगाल के साथ समझौता कुछ संदर्भो में समाप्त और वहाँ के रास्ते से आने वाले निवेश पर पूंजी लाभ कर (Capital Gain Tax) लागू

55

7.

1997

Asia - Pacific Group
↓
FATF के तर्ज पर आतंकवाद के वित्तीय स्रोत तथा धनशोधन पर नियंत्रण हेतु 1997 में स्थापित एक क्षेत्रीय संगठन

(41 देश सदस्य और 2021 में भारत सदस्य)

60

10.

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सहमति कायम करने का प्रयास

61

11.

जून 2017

भारत एवं अन्य देशों के दबाव में स्विटजरलैंड द्वारा अपनी बैंकिंग गोपनीयता संबंधित कानून में संशोधन- जिससे स्विटजरलैंड के स्विस बैंक में काला धन जमा करने वालों की जाँच में सहयोग सम्भव हो सकेगा, साथ ही स्विस बैंक द्वारा 2018 के बाद अपने बैंकों में खोले गये सभी खातों एवं निवेश के बारे में सूचना साझा किया जाएगा

62

(B) राष्ट्रीय प्रयास

63

1.

1956

प्रवर्तन निर्देशालय

Enforcement Directorate

(ED)

64

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक बहु-अनुशासनिक संगठन जो धन-शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच के लिए अधिदेशित है और जो निम्न विधियों को लागू कराती है–

1. FEMA - 1999
2. PMLA - 2003
3. FEOA - 2018

65

प्रमुख कार्य

1. FEMA – 1999 के उल्लंघन से संबंधित सूचना का संग्रहण, विकास और प्रचार-प्रसार करना
2. हवाला, विदेशी मुद्रा, धोखा-धड़ी, निर्यात आय की वसूली न किया जाना, विदेशी मुद्रा को वापस लाया जाना जैसे गतिविधियों और FEMA - 1999 के उपबंधों के उल्लंघन की जाँच पड़ताल करना

66

3. पूर्ववर्ती FERA – 1973 और FEMA – 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्याय निर्णय करना
4. न्याय निर्णयन कार्यवाहियों का समापन पर लगाई गई दण्ड शास्तियों की वसूली करना
5. FEMA – 1999 के तहत न्याय निर्णयन, अपील और अभियोजन संबंधी मामले को निपटाना

67

6. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक रोक के लिए कार्यवाही करना
7. Prevention of Money Laundering Act के तहत अपराध करने वालों के विरूद्ध सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन संबंधी कार्यवाही करना

68

8. FEOA के तहत भगोडे आर्थिक अपराधी की संपत्तियों को कुर्क करना
9. अपराधिक कार्यवाहियों तथा PMLA के तहत आरोपित व्यक्तियों के प्रत्यार्पण और उनकी जब्ती से संबंधित मामलों में संबंधित देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना

69

FERA

stands for

Foreign Exchange Regulation Act

2.

1973

FERA

70

3.

1985

Central Economic Intelligence Bureau

(CIEB)

71

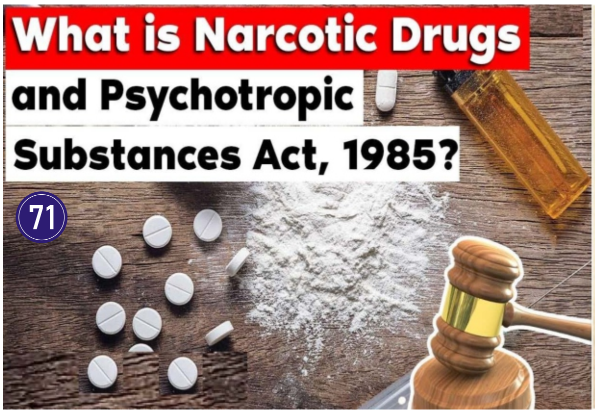

4.

1985

नशीले पदार्थो की तस्करी निरोधक अधिनियम

72

5.

1988

बेनामी लेन-देन निषेध अधिनियम

73

6.

1988

Prevention of Corruption Act, 1988

74

7.

1999

FEMA

75

8.

2003

प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट

(2012 में संशोधन)

76

Dr. S. S. Pandey

Prevention of Money Laundering Act

PMLA - 2003 / 2012

↓

77

78

प्रमुख प्रावधान

(i) धन को छुपाना (Concealment), अधिग्रहण (Acquisition) कब्जा करना (Possession), धन का अपराधिक कार्यों में प्रयोग, हवाला आदि सभी मनी-लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में शामिल–

(ii) Money Laundering में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होना अपराध

79

(iii) Money Laundering के अपराध के लिए 10 वर्ष तक सजा और संपत्ति की जब्ती एवं कुर्की का प्रावधान

(iv) 'निर्णय/नियमन प्राधिकरण' (भाग-6) एवं 'अपील प्राधिकरण' (भाग 25) के गठन का प्रावधान

(v) Money Laundering के अपराध की जाँच हेतु 'विशेष न्यायालय प्राधिकरण' के गठन का प्रावधान

80

(vi) सीमा पार के जटिल स्वरूप वाले तथा आतंकवाद का वित्तपोषण करने वाले अपराधों से निपटने का विशेष प्रावधान

(अनुबंधित देशों में कुर्की एवं अधिग्रहण का प्रावधान यदि द्विपक्षीय संधि हुई हो)

↓

अब सीमा पार के किए गए Money Laundering को भारत में PMLA के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जायगा

81

(vii) प्रवर्तन निर्देशालय का सशक्तिकरण तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद जाँच का प्रावधान

(viii) प्रत्यक बैंकिंग कम्पनी को अपने ग्राहकों का रिकॉर्ड रखना जरूरी

(ix) भुगतान प्रणाली [Master Card, Credit Card] संचालकों के Regulation का प्रावधान

82

9.

2004

वित्तीय खूफिया ईकाई (FIU) [Financial Intelligence Unit]

83

(i) संदेहास्पद लेन-देन की सूचना प्राप्त करने वाली एक स्वायत निकाय जिसका गठन 2004 में

(ii) यह Money Laundering से संबंधित मामलों में वैश्विक समन्वय की भूमिका में

84

(iii) यह संदेहस्पह लेन-देन के विश्लेषण एवं समाधान हेतु तीन तरह की रिपोर्टिंग के लिए आदेश जारी करती है

- नगदी लेन-देन का रिपोर्ट
- संदेहास्पद लेन-देन का रिपोर्ट
- नकली मुद्रा रिपोर्ट

85

10.

2004

SEBI द्वारा PMLA के तहत SEBI के अन्तर्गत पंजीकृत मध्यस्थ को निवेशकों के बारे में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य कर दिया गया

86

11.

2013

2013 में RBI द्वारा Master Circular जारी

(इसमें बैंकों को अपने ग्राहकों के बारे में जानने और उनकी सूचनाओं को अपडेट करने का निर्देश दिया गया)

87

12.

1 जुलाई 2015

काला धन

(अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम 2015 लागू

88

इस कानून के तहत प्रावधान किया गया कि–

(i) अगर किसी के पास विदेशों में अघोषित सम्पत्ति हैं तो उसे 90 दिन की अनुपालन अवधि (1 जुलाई 2015 से 30 सितम्बर 2015) के दौरान इसकी घोषणा करने पर कुल सम्पत्ति का 60% की दर से कर और जुर्माना (30% कर + 30% जुर्माना) देय होगा

89

(ii) 30 सितम्बर तक की अवधि बीत जाने के बाद विदेशों से आय या सम्पत्ति पर 120% जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान

इस योजना के तहत 30 सितम्बर 2015 तक 638 खुलासे के द्वारा कुल 3770 करोड़ की प्राप्ति हुई

[जबकि सरकार का अनुमान था 6500 करोड़]

90

13.

29 Feb. 2016

केन्द्र सरकार द्वारा देश के भीतर के काला धन की निकासी हेतु 'कालाधन क्षमा योजना' (Black Money Declaration Scheme) प्रारम्भ की गयी

91

इस योजना के तहत –

1 जून 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक की अवधि में देश के भीतर काला धन / अघोषित सम्पत्ति की घोषणा करने पर 45% कर एवं जुर्माना (30% कर + 7.5 कृषि कल्याण अधिभार + 7.5% जुर्माना) देय होगा और धन के स्रोत की पूछताछ एवं जाँच नहीं की जायेगी

92

30 सितम्बर 2016 के बाद इस सम्पत्ति पर 120% जुर्माना तथा 10 साल तक की सजा का प्रावधान

(सरकार की इस योजना के तहत विभिन्न घोषणाओं के द्वारा लगभग 65 हजार करोड की घोषणा हुई)

93

14.

1 Nov. 2016

Benami Transaction (Prohibition) Act, 2016

(यह अधिनियम सर्वप्रथम 1988 में पारित तथा 2016 में संशोधन)

94

प्रमुख प्रावधान

(i) केन्द्र सरकार द्वारा बेनामी संपत्तियों को जब्त करने एवं उन्हें साबित करने का अधिकार का प्रावधान

(ii) बेनामी लेन-देन करने वालों पर अभियोजन एवं दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान

(तीन से सात वर्ष की कैद या संम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 25% जुर्माना या दोनों)

(iii) बेनामी संपत्ति की गलत सूचना देने पर संपत्ति के बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना का प्रावधान

95

15.

2016

Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016

96

16.

8 Nov. 2016

भारत सरकार द्वारा नोटबंदी

97

17.

1 April 2017

आयकर संशोधन अधिनियम

98

प्रमुख प्रावधान

(i) व्यक्ति द्वारा अपनी अघोषित आय की घोषणा करने पर कर एवं जुर्माना के रूप में 50% देय और एसा नहीं करने पर तथा पकड़े जाने पर 85% कर एवं जुर्माना देय

(ii) घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25% 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' में लगाना होगा। जहा कोई ब्याज नही मिलेगा और इस राशि को 4 साल तक नहीं निकाला जा सकेगा

99

(iii) अगर व्यक्ति अपनी अघोषित आय का स्रोत नहीं बताना चाहता है तो उसे कुल अघोषित आय पर 60% Tax + 15% सरचार्य +3% उपकर देय होगा

100

18.

23 August 2017

सालाना 2 करोड रूपये से अधिक Turnover वाले ज्वेलर्स PMLA के दायरे में

101

19.

19 May 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 2000 रुपया के नोट को बंद करने का निर्णय

31 सितंबर 2023 को बंद

102

भारत में मनीलॉन्ड्रिंग रोकने के समक्ष चुनौतियाँ / बाधाएँ

103

1.

सरकारी नियम एवं बैंकिंग जटिलताएँ

104

2.

विदेशी निवेश के प्रोत्साहन हेतु शेयर बाजार में गैर संस्थागत विदेशी निवेश संबंधी SEBI के नियमों में ढीलाई और अन्य प्रतिबंधों को हटाया जाना

105

3.

बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा KYC का उल्लंघन

106

4.

तकनीकी विकास, विशेष रूप से साइबर टेक्नोलॉजी में तीव्र विकास और इस विकास के अनुरूप कानून निर्माण का अभाव

107

5.

DTAA का विस्तार तथा Tax Haven Country और इन देशों में बैंकिंग गोपनीयता से संबंधित विशेष कानून

108

6.

तस्करी, अवैध व्यापार एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि फलतः काले धन में वृद्धि

109

7.

भारत जैसे विकासशील देशों में जागरूकता की कमी

110

मनीलॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु सुझाव

111

1.

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसे कानून का निर्माण किया जाए तथा Interpol जैसी संस्थाओं का प्रयोग किया जाए

112

2.

अन्तर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से वित्तीय सूचनाओं को साझा करने और शामिल अपराधियों के प्रत्यार्पण की समुचित एवं त्वरित व्यवस्था

113

3.

तकनीकी विकास एवं आर्थिक जटिलताओं के अनुसार संबंधित कानून में संशोधन, संबंधित जाँच एजेंसियों के मध्य समन्वयन एवं आर्थिक जटिलताओं का सामान्यीकरण

114

4.

DTAA का पुनर्निरीक्षण

115

5.

Tax Heaven Country या स्विस बैंक जैसे बैंकों की गोपनीयता से संबंधित प्रावधानों को बदला जायें और Money Laundering के जाँच के क्रम में जाँच एजेसीयों को सभी आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाये

116

6.

समुचित कानून के द्वारा तथा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसके पालन द्वारा तस्करी, संगठित अपराध एवं काला धन पर नियंत्रण किया जाये और इस हेतु सुरक्षा बल एवं संबंधित एजेसियों के आधुनिकीकरण एवं सशक्तिकरण के द्वारा, सीमा सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाये

117

संभावित प्रश्न

118

- भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के प्रचलित स्वरूपों की चर्चा करें। इसने भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कौन-सी चुनौती प्रस्तुत की है?

119

- भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग ने अनेक प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न किया है। भारत सरकार द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

120

- भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग का सीमा पारीय आतंकवाद एवं संगठित अपराध के साथ संबंधों की विवेचना करें एवं इसके प्रबंधन हेतु उपाय सुझाय।

121

- भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए और इस दिशा में साइबर सुरक्षा के उपायों को स्पष्ट कीजिए।

122

- PMLA - 2012 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें और मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने में इसकी प्रासंगिकता को बतायें।

123

UPSC - CSE में
विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

124

- चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी-लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी-लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए) 10/2021

Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money-laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money-laundering both at national and international levels. (Answer in 150 words) 10/2021

125

- अवैध धन स्थांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? (उत्तर 200 शब्दों में दें) 10/2013

Money laundering poses a serious threat to country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace? (Answer in 200 words) 10/2013